5 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट की इजाजत

दाम काबू में करने के लिए सरकार का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का फैसला

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

सरकार ने 12 जून तक 5 लाख टन तक कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दी है। इससे भारत में चीनी की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे इसके दाम को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। ट्रेडर्स और मिल मालिकों का कहना है कि इस फैसले से चीनी के दाम पर दबाव बढ़ सकता है।

मुंबई के होलसेल मार्केट में बुधवार को चीनी की कीमत 38.50 रुपये प्रति किलो चल रही थी। हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के दाम गिर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद चीनी की कीमत में 3.7 पर्सेंट की गिरावट आई और यह 16.75 सेंट पर पहुंच गई। ट्रेडर्स का कहना है कि इस प्राइस पर भारत में विदेशी चीनी की कीमत 34 रुपये प्रति किलो पड़ेगी।

संसद में पेश किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, '12 जून तक 5 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट की इजाजत दी जाती है। इस नोटिफिकेशन पर 5 अप्रैल की तारीख दी गई है। कच्ची चीनी के आयात की इजाजत टैरिफ रेट कोटा के तहत दी गई है।' भारत में दुनिया में सबसे अधिक चीनी की खपत होती है। यहां सालाना 2.5 करोड़ टन चीनी की मांग है। जब कभी देश में शुगर प्रॉडक्शन घटता है, तब विदेशी बाजारों से इसका आयात करना पड़ता है। सरकार अक्सर डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम को कंट्रोल करने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करती आई है।

भारत में दुनिया में सबसे अधिक चीनी की खपत होती है। यहां सालाना 2.5 करोड़ टन चीनी की मांग है

सरकार के इस फैसले पर ईडीएंडएफ मैन कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख ने कहा, 'मार्केट में चीनी की सप्लाई टाइट है। इसलिए सरकार ने सही कदम उठाया है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की जो कीमत है, उस हिसाब से देश में मंगाने पर इसकी लागत 34-35 रुपये किलो पड़ेगी। वहीं, डोमेस्टिक मार्केट में एवरेज प्राइस 37 रुपये किलो है।' सरकार ने इस साल शुगर प्रॉडक्शन का टारगेट 2.25 करोड़ टन रखा है, जबकि पिछले सीजन में यह 2.51 करोड़ टन था। उसकी वजह यह है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यील्ड कम हुई है। भारत ने 2016-17 सीजन की शुरुआत 77.5 लाख टन चीनी के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ की थी।

ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल विठलानी ने बताया कि 5 लाख टन के इंपोर्ट से मार्केट में चीनी की सप्लाई ठीक बनी रहेगी। इससे चीनी की कीमत स्टेबल बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'सरकार मॉनसून सीजन पर नजर रखेगी। अगर अल निनो का असर दिखता है तो वह और अधिक चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे सकती है।' उन्होंने यह भी बताया कि एसोसिएशन नोटिफिकेशन पर स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही है। कच्ची चीनी के आयात से श्री रेणुका शुगर्स, ईआईडी पैरी, सिम्भावली शुगर्स जैसी कंपनियों को फायदा होगा, जिनके प्लांट बंदरगाहों के पास हैं।

The economic Times.
6-4-17.